TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 219
दि. 10.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

माइक्रोसॉफ्ट का भारत में ऐतिहासिक दांव; ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश करेगा

■ टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने अब तक के सबसे बड़े निवेश की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह एलान किया।

नई दिल्ली (जीएनएस)।भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नए युग की शुरूआत का संकेत देते हुए, टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने अब तक के सबसे बड़े निवेश की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम बैठक के बाद, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने बुधवार को एलान किया कि कंपनी भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपये (लगभग 17.5 बिलियन डॉलर) का निवेश करेगी।

एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल इन्वेस्टमेंट भारत में

यह एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल इन्वेस्टमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का यह फैसला बताता है कि दुनिया में तकनीक के मामले में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। बैठक के बाद सत्या नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा नडेला ने लिखा, " बुधवार शाम को हुई इस मुलाकात ने न केवल भारत-अमेरिका तकनीकी संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि भारत की एआई महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान दी है।"

नडेला ने कहा, "भारत में एआई अवसरों पर एक प्रेरणादायक बातचीत के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट 17.5 अरब डॉलर (लगभग ₹1.5 लाख करोड़) के निवेश का वादा रहा है- यह एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह निवेश भारत के 'एआई-फर्स्ट भविष्य' के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगा।"

एआई की बात आती है तो दुनिया भारत को लेकर आशान्वित

नडेला के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "जब बात एआई की आती है तो दुनिया भारत को लेकर आशान्वित है। सत्या नडेला के साथ बहुत ही उत्पादक चर्चा हुई।

यह देखकर खुशी हो रही है कि भारत वह स्थान बन रहा है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना सबसे बड़ा निवेश करेगा। भारत के युवा इस अवसर का उपयोग नवाचार करने और एक बेहतर ग्रह के लिए एआई की शक्ति का लाभ उठाने में करेंगे।" माइक्रोसॉफ्ट की ऐतिहासिक घोषणा का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की युवा शक्ति और नवाचार क्षमता पर भरोसा जताया।

सीएम योगी ने जनरल रावत को बताया राष्ट्र का महान योद्धा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें राष्ट्र का महान योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि जनरल रावत को बताया राष्ट्र का महान योद्धा, कर्तव्य सर्वोपरि, वीरों की स्मृति प्रेरणा

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने मंगलवार को सैनिक स्कूल परिसर में देश के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के नाम पर निर्मित प्रेक्षागृह तथा उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने जनरल रावत को राष्ट्र का महान योद्धा बताया।

कहा कि हर भारतवासी का दायित्व है कि ऐसे वीरों के योगदान को सदैव स्मरण रखे। सीएम सैनिक स्कूल प्रशासन से अपेक्षा जताई कि स्कूल में प्रतिवर्ष आठ दिसंबर को जनरल रावत और उनके साथ शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में प्रेरणा दिवस मनाया जाए, ताकि कैडेट्स में राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यपरायणता की भावना मजबूत हो।

योगी ने कहा कि जनरल रावत पद और प्रतिष्ठा से कहीं अधिक सहज, सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व थे। वह मातृभूमि के प्रति समर्पण और शौर्य की अद्भुत मिसाल थे। उन्होंने गोरखपुर तथा उत्तराखंड में हुई अपनी कई मुलाकातों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनरल रावत की विनम्रता और दृढ़ इच्छाशक्ति युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगी।

कार्यक्रम में सीएम योगी ने श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक- 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्' का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संदेश केवल सैनिकों ही नहीं, प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए पंच प्रण का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास के लिए हर भारतीय को अपनी विरासत पर गर्व करना होगा और अपने कर्तव्यों को जीवन का मूल सिद्धांत बनाना होगा।

मुख्यमंत्री बताया कि एक बार उन्होंने जनरल रावत से कठिन परिस्थितियों में सैन्य सेवा का रहस्य पूछा तो उन्होंने गीता का मंत्र- 'योगः कर्मसु कौशलम्' और 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' उद्धृत करते हुए निष्काम कर्म की प्रेरणा को अपनी शक्ति बताया।

उन्होंने कहा कि देश वही महान होता है जहां नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं। केवल अधिकारों की मांग करने वाली मानसिकता और ट्रेड यूनियन संस्कृति ने कई संस्थानों को नष्ट किया है। इस क्रम में उन्होंने गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का उदाहरण दिया।

मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन और आयोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रप्रेम और बलिदान की भावना को और मजबूत करते हैं।

राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए

■ राष्ट्रपति ने कहा - हस्तशिल्प कलाएं न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं, बल्कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं

■ राष्ट्रपति ने कहा - हस्तशिल्प क्षेत्र युवा उद्यमियों और डिजाइनरों को उद्यम स्थापित करने के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है

(जीएनएस) ।राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (9 दिसंबर, 2025), नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि कला हमारे अतीत की स्मृतियों, वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य चित्रकला या मूर्तिकला के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता रहा है।

कला लोगों को संस्कृति से जोड़ती है। कला लोगों को एक-दूसरे से भी जोड़ती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा के जीवंत और संरक्षित रहने का श्रेय, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कारीगरों की प्रतिबद्धता को जाता है। हमारे कारीगरों ने अपनी कला और परंपरा को समय के साथ ढाला है और साथ ही मूल भावना को भी जीवित रखा है। उन्होंने अपनी प्रत्येक कलात्मक रचना में देश की मिट्टी की खुशबू को संजोकर रखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हस्तशिल्प न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं, बल्कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। यह क्षेत्र देश में 32 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प से रोजगार और आय प्राप्त करने वाले ज्यादातर लोग ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं।

184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र ने किए 1700 करोड़ मंजूर

उत्तराखण्ड की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 1700 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। हाल की प्राकृतिक आपदा से 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रदेश की कृषि व्यवस्था, ग्रामीण विकास, हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि

सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और ऐसी स्थिति में केंद्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है, ताकि प्रभावित अवसंरचना का त्वरित पुनर्निर्माण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने हाल की आपदा से क्षतिग्रस्त लगभग 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी उत्तराखण्ड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति एक गंभीर चुनौती है।

इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)- डी.पी.आर. योजना के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने फसलों की सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए अलग से बजट की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आगामी पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था करने का आग्रह किया।

इस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया, जिससे घेराबंदी कार्य व्यापक स्तर पर शुरू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान हेतु वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लिया जाएगा तथा केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में 'जल शक्ति हैकाथॉन-2025' का शुभारंभ किया

■ जल शक्ति हैकाथॉन-2025 जल-सुरक्षित भारत के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलनः सीआर पाटिल

(जीएनएस) ।केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में 'जल शक्ति हैकाथॉन-2025' और भारत-विन पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और भारत के जल क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी समाधानों को मजबूत करने के लिए उनके 'जल विजन@2047' पर जोर के अनुरूप है।

श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल शक्ति हैकाथॉन-2025 महज एक प्रतियोगिता नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। इसे भारत के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित जल भविष्य के निर्माण हेतु देश की सामूहिक प्रतिभा को जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है।

राष्ट्रीय भागीदारी के लिए एक सार्वजनिक भलाई

हैकाथॉन का उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसे सभी हितधारकों के लिए एक वास्तविक सार्वजनिक हित बनाना है। यह समग्र सरकार और समग्र समाज (जनभागीदारी) दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे नागरिकों, शोधकताओं, उद्योगों और नवप्रवर्तकों की व्यापक भागीदारी संभव हो सके।

https://bharatwin.mowr.gov.in पर उपलब्ध यह पोर्टल राष्ट्रीय मंच भारत-विन (जल नवाचार नेटवर्क) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर की जल चुनौतियों के लिए व्यावहारिक, मापनीय और क्षेत्र-तैयार समाधानों को बढ़ावा देना है। इनमें खेत-स्तर पर जल संरक्षण, ग्रामीण जल गुणवत्ता, स्मार्ट निगरानी, पारंपरिक जल व्यवस्थाओं का पुनरुद्धार, बाढ़ और सूखा प्रबंधन शामिल हैं।

यह पहल जल-क्षेत्र अनुसंधान के दायरे को सीमित संस्थानों से आगे बढ़ाती है।

मुख्यमंत्री-उप मुख्यमंत्री ने एसीबी में उत्तम कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों का तथा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध शिकायत कर उन्हें गिरफ्तार करवाने वाले साहसी नागरिकों का सम्मान किया

- 'सतर्कता हमारी संयुक्त जिम्मेदारी' के सूत्र के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता अभियान में वक्तव्य एवं निबंध प्रतियोगिताओं के 12 विजेता छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- अधिकार से बाहर का नहीं लेना चाहिए; यह हमारी संस्कृति की विरासत के संस्कार हैं
- जो कार्य या ड्यूटी करें, उससे आत्मसंतोष हो; वही सच्ची कर्तव्यनिष्ठा
- भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) की छवि ऐसी हो कि गलत करने वाले को सतत भय रहे कि गलत हो ही नहीं
- अनिवार्य सेवानिवृत्ति के ऐतिहासिक आँकड़े मृदु एवं दृढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आक्रामक रुख दर्शाते हैं : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

गांधीनगर, 09 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर गुजरात राज्य भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) द्वारा गांधीनगर में आयोजित समारोह में कहा कि एसीबी किसी गरीब की सहायक होने का भाव उजागर करने के लिए कार्य करने वाला विभाग है।

श्री पटेल ने कहा कि हम जो कार्य करें या ड्यूटी निभाएँ, उससे आत्मसंतोष हो; ऐसी हमारी कर्तव्यनिष्ठा हो, जिससे यह भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाना ही न पड़े। उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ वातावरण निर्मित करने की भी प्रेरणा दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में आयोजित समारोह में एसीबी में उत्तम कार्य करने वाले लगभग 10 कर्मचारियों-अधिकारियों का सम्मान किया। इतना ही नहीं; किसी न किसी कार्य के लिए रिश्वत मांगने वाले भ्रष्टाचारी अधिकारियों का पदार्फाश कर एसीबी में उनके विरुद्ध आवाज उठा कर तथा शिकायत कर उन्हें गिरफ्तार करवाने वाले 4 साहसी नागरिकों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत सतर्कता सप्ताह के दौरान आयोजित निबंध एवं वक्तव्य प्रतियोगिताओं के विजेता 12 छात्रों को प्रमाणपत्र भी इस अवसर पर प्रदान किए गए।

सम्पादकीय

इंडिगो के संकट का निपटान नहीं हो सका

इंडिगो संकट–अभी ज्यादातर एयरलाइंस 'जैसेतैसे' काम चला रही हैं। उनको सख्ती से पायलटटू– कॉकपिट रेशियो और ड्यूटी टाइम लिमिट लागू करानी होगी। यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करना होगा। सरकार को जल्दी से 'यात्री अधिकार चार्टर' लागू करना चाहिए। भारतीय एविएशन के सुनहरे भविष्य के लिए यह सही वक्त है कि सबक लिया जाए और सुधार शुरू किया जाए।

इंडिगो संकट–हवाई मुसाफिरों की सुनो पिछले कुछ दिनों से भारत का एविएशन सेक्टर घुटनों पर आ चुका है। देश–दुनिया के लाखों यात्री इंडिगो एयरलाइंस की हजारों फ्लाइट्स के कैंसिल होने के कारण धक्के खा रहे हैं। यह घटना सिर्फ इंडिगो की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर की कमजोर किड़यों को उजागर करती है। एक तरफ हम 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ बुनियादी समस्याएं जस की तस हैं। पर इंडिगो एयरलाइंस के प्रमोटर राहुल भाटिया का कहीं पता नहीं चल रहा है। कौन हैं राहुल भाटिया? उन्हें और उनके पिता कपिल भाटिया को करीब से जानने बताते हैं कि मूल रूप से राजधानी के सदर बाजार के बस्ती हरपूल सिह से हैं। इनका पहला दफ्तर सदर बाजार में ही था। वहां पर पिता–पुत्र एयरलाइंस की टिकटें बेचा करते थे। पर इन्हें जल्दी समझ आ गया कि एयरलाइंस के बिजनेस को करने के लिए किसी बेहतर जगह में दफ्तर शुरू करना लाजिमी है। इसलिए ही इन्होंने कनॉट प्लेस के पी ब्लॉक में ऑफिस शुरू किया। उसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वायुदूत एयरलाइंस के फाउंडर चेयरमैन हर्षवर्धन कहते हैं कि राहुल भाटिया आगे इसलिए बढ़े क्योंकि इन्होंने सही वत्त पर सही पैसले लिए। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उनके लिए आने वाले वाला समय आसान नहीं होगा। आपको कनॉट प्लेस के 'पी' ब्लॉक में अब भी बहुत से शो–रूम और उनमें काम करने वाले मुलाजिम मिल जाएंगे जिन्होंने राहुल भाटिया को अपने पिता कपिल भाटिया की ट्रेवल एजेंसी दिल्ली एक्सप्रेस' में आते–जाते देखा है। 'दिल्ली एक्सप्रेस' का दफ्तर अब बंद हो गए मद्रास होटल के पास ही था। ये 1980 और 1990 के दौर की बातें हैं। राहुल भाटिया तब कनाडा में पढ़ रहे थे। वे दिल्ली आते तो अपने दफ्तर में बैठते भी। उस दौर में अपने देश में गिनती के ही लोग तो विमान से सफर किया करते थे। दिल्ली एक्सप्रेस का काम ठीक–ठाक था। दिल्ली एक्सप्रेस वुछ अतर्राष्ट्रीय एयरलाइंसों की एजेंट थी। आप कह सकते हैं कि यह सिर्फ इन्हीं एयरलाइंसों की टिकट बुक किया करती थी। आर्थिक उदारीकरण के बाद देश के एविएशन सेक्टर की तस्वीर बदलने लगी। अब पिता कपिल भाटिया के साथ राहुल भाटिया पूरी तरह से सहयोग करने लगे। वो कनाडा से वापस आए गए थे। राहुल भाटिया ने कनाडा से मैनेजमेंट की डिग्री ली थी। वो संतुष्ट नहीं थे अपनी ट्रेवल एजेंसी की ग्रोथ से। वो बड़ी छलांग लगाना चाहते था। इसी दौरान, भाटिया परिवार ने अपनी दिल्ली एक्सप्रेस अपने पार्टनर को बेचकर नई कंपनी इंटर ग्लोब ट्रेवल एजेंसी खोली। इसका काम चमकने लगा। इस बीच,सरकार ने 1993 में देश में प्राइवेट एयरलाइंस को शुरू करने के लिए लाइसेंस देने शुरू किए। इसके बाद मोदीलुफ्त, डेक्कन एविएशन,जेट एयरवेज वगैरह शुरू हुईं। ये सब राहुल भाटिया देख रहे थे। उनका भी अरमान था कि वे भारत में अपनी एयरलाइंस शुरू करें। कनॉट प्लेस में भाटिया परिवार के पड़ोसी रहे रज्जी राय बताते हैं कि राहुल भाटिया बहुत महत्वांकाक्षी थे। उन्होंने अपने अमेरिका में रहने वाले दोस्त राकेश गंगवाल से नई एयरलाइंस शुरू करने के बारे में बात की। दोनों ने अपनी योजना पर काम किया। राकेश फाइनेंस मामलों के एक्सपर्ट थे। आखिर इनका वत्त आया 2006 में। इन्होंने इंडिगो एयरलाइंस लांच कर दी। 65 फीसद बाजार पर कब्जा – राहुल भाटिया के पार्टनर राकेश गंगवाल ने वुछ समय पहले अपनी इंडिगो की हिस्सेदारी बेच दी है। मतलब अब वे इंडिगो के एकछत्र मालिक हैं। एविएशन सेक्टर के जानकार और चार्टर्ड एकाउंटेंट राजन धवनने राहुल भाटिया को तब से देखा है जब वे कनॉट प्लेस से ऑपरेट करते थे। वे कहते हैं कि इंडिगो के हालिया व्रइसिस से इसकी इमेजबुरी तरह सेखराब हुई है। अब इसे सरकार की सख्ती का सामना करना पडेगा। राहुल भाटिया को जवाब देना होगा कि उनकी एयरलाइंस की करतूत के कारण भारत के एविशन सेक्टर की इमेज को कितना झटका लगा है। उन्हें हैरानी इस बात की है कि वे अपनी तरफ से वुछ भी नहीं बोल रहे।

मुसाफिरों से माफी नहीं मांग रहे।

गुजरात का 'ब्लू फ़्लैग शिवराजपुर बीच' बना वैश्विक 'बीच टूरिज्म' का नया प्रतीक, वीजीआरसी-2026 में कच्छ-सौराष्ट्र बनेंगे निवेश केंद्र

- शिवराजपुर बीचः गुजरात के 'बीच टूरिज्म' का नया वैश्विक प्रतीक, ब्लू फ्लैग प्रमाणन ने बढ़ाई अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा
- शिवराजपुर बीच के आसपास 130 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होटल, एडवेंचर टूरिज्म, सांस्कृतिक–अनुभवात्मक प्रोजेक्ट्स से बढ़ेंगे निवेश के अवसर
- VGRC, राजकोट में पहली बार कच्छ–सौराष्ट्र पर्यटन सर्किट का समग्र निवेश रोडमैप होगा पेश

गांधीनगर, 09 दिसंबर :गुजरात का पर्यटन परिदृश्य आज एक नए वैश्विक मानक की ओर अग्रसर है, और इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है देवभूमि द्वारका स्थित शिवराजपुर बीच का अद्भुत कायाकल्प जो राज्य का पहला ग्लोबल ब्लू फ्लैग बीच बनने का गौरव प्राप्त कर चुका है। यह उपलब्धि न केवल गुजरात की तटीय सुंदरता को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला रही है, बल्कि राज्य में विश्वस्तरीय, टिकाऊ और आधुनिक पर्यटन अवसंरचना विकसित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'देखो अपना देश' विजन को साकार करते हुए, शिवराजपुर बीच का यह परिवर्तन घरेलू पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता तक पहुँचाने की गुजरात की दूरदर्शी सोच को दशार्ता है जहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक बिना विदेश जाए विश्वस्तरीय समुद्र तट अनुभव का आनंद ले सकता है।

शिवराजपुर बीचः ब्लू फ़्लैग प्रमाणन के साथ गुजरात का नया वैश्विक तटीय गौरव

गुजरात की 2340 किमी लंबी तटरेखा पर स्थित शिवराजपुर बीच अपनी स्वच्छता, सुरक्षा और प्राकृतिक शांतिमय सौंदर्य के कारण देश–विदेश में पहले से ही विशिष्ट पहचान रखता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन ने इसे विश्वस्तरीय समुद्र तटों की श्रेणी में शामिल करते हुए एक प्रतिष्ठित गौरव प्रदान किया है। यह प्रमाणन न केवल पर्यावरणीय प्रबंधन और सुरक्षा मानकों का प्रमाण है, बल्कि गुजरात द्वारा विकसित की जा रही आधुनिक सुविधाओं और टिकाऊ तटीय अवसंरचना की सफलता का भी सशक्त संकेत है। गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (ळउत्र्छ) द्वारा 130 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित यह मॉडल प्रोजेक्ट अब राज्य के पर्यटन क्षेत्र की नई पहचान बन चुका है। यही सफलता आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (श्त्र्क्ष्ळ) राजकोट में केंद्र बिंदु बनने जा रही है, जहाँ कच्छ–सौराष्ट्र की तटीय और सांस्कृतिक बेल्ट में व्यापक निवेश अवसरों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है शिवराजपुरः निवेश और इवेंट टूरिज्म का उभरता केंद्र

ळउत्र्छ द्वारा तैयार की गई विकास परियोजनाओं में अत्याधुनिक अराइवल प्लाजा, स्नॉर्कलिंग प्लाजा, साइकिल ट्रैक, प्रोमेनेड, स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएँ शामिल हैं, साथ ही 11 किमी से अधिक लंबी नई सड़क ने इस तटस्थल तक पहुँच और बेहतर बना दी है। शिवराजपुर बीच को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने हेतु चेंजिंग रूम, शावर रूम, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी आवश्यक सुविधाएँ भी विकसित की गई हैं। आने वाले महीनों में प्रस्तावित 'बीच फेस्टिवल' और विभिन्न थीम–आधारित तटीय आयोजनों की शुरूआत, शिवराजपुर को एक अंतरराष्ट्रीय तटीय इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने जा रही है। वहीं, द्वारका–ओखा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा द्वारका, बेट द्वारका और शिवराजपुर के एकीकृत पर्यटन क्षेत्र के लिए बनाई जा रही व्यापक योजनाएँ इस पूरे सर्किट को राज्य के प्रमुख निवेश और पर्यटन विकास केंद्र में परिवर्तित करने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होंगी।

आगामी श्त्र्क्ष्ळकच्छ–सौराष्ट्र के पर्यटन परिदृश्य में खोलेगा निवेश के नए स्वर्णिम द्वार

10, 11 और 12 जनवरी 2026 को राजकोट में होने जा रहा वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (श्त्र्क्ष्ळ) कच्छ–सौराष्ट्र पर्यटन सर्किट को केंद्र में रखते हुए प्रदेश के तटीय पर्यटन विकास के लिए एक निर्णायक मंच बनने जा रहा है। शिवराजपुर बीच का विश्वस्तरीय कायाकल्प इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन निवेश की अपार संभावनाओं का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है, जिसके आधार पर गुजरात सरकार निवेशकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने की तैयारी में है।

श्त्र्क्ष्ळ सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत के अग्रणी निवेशकों और रणनीतिक साझेदारों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे देवभूमि द्वारका में प्रीमियम कोस्टल रिसॉर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स और तटीय एडवेंचर प्रोजेक्ट्स, कच्छ–सौराष्ट्र में इको–टूरिज्म और हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी, गिर क्षेत्र में वन आधारित पर्यटन तथा रण में सांस्कृतिक–अनुभवात्मक पर्यटन जैसे हाई–रिटर्न अवसरों में निवेश करें।

इंडिगो की डूबी लुटिया? केंद्र का 10% कटौती का फरमान-यात्रियों पर क्या पड़ेगा असर?

(एजेंसी)। हवाई सफर का सपना टूटते हुए देखा है? हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे, बैग गुम, रिफंड का इंतजार – यह सब हाल ही की इंडिगो की उड़ान रद्दीकरण वाली त्रासदी है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को अपने परिचालन में 10% की कटौती का आदेश दिया है।

इसका मकसद है– एयरलाइन के बढ़ते कैंसिलेशन को रोकना और सिस्टम को स्थिर करना। लेकिन क्या इससे आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा या टिकट सस्ते होंगे? आइए, इस एक्सप्लेनर में पूरी स्टोरी को समझें – वजह, फैसला, रिफंड की स्थिति और आम आदमी पर असर...

क्यों फंसे लाखों यात्री?

पिछले हफ्ते से इंडिगो की उड़ानें अस्त–व्यस्त हो गईं। 2 दिसंबर से शुरू हुए इस 'मेल्टडाउन' में क्रू शॉर्टेज, नए फ्लाइट ड्यूटी नियमों की वजह से रद्दीकरण बढ़ गए। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक, 1–7 दिसंबर तक 5,86,705 PNR रद्द हुए, जिनका रिफंड ₹569.65 करोड़ का हुआ। कुल मिलाकर, 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9,55,591 PNR रद्द, रिफंड ₹827 करोड़।

सबसे ज्यादा मार पड़ी दिल्ली (152 रद्द), बेंगलुरु (121), हैदराबाद और चेन्नई पर। 5 दिसंबर

को तो सिर्फ 700 उड़ानें ही उड़ीं, जबकि सामान्य 2,200। इंडिगो का 65% मार्केट शेयर होने से पूरे एविएशन सेक्टर में हड़बड़ी मच गई। यात्री फंसे, बैग गुम – कुल 9,000 बैग प्रभावित, जिनमें से 4,500 डिलीवर हो चुके। बाकी 36 घंटे में पहुंचाने का वादा।

10% कटौती का आदेश कैसे आया?

यह सब एक हाई–लेवल मीटिंग का नतीजा है। मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंत्रालय बुलाया। सचिव सामी र सिन्हा के साथ बैठक में तय हुआ – इंडिगो को विन्टर शेड्यूल में 10% रूट्स कट करने पड़ेंगे। पहले DGCA ने 5% कट का आदेश दिया था, लेकिन मंत्रालय ने इसे दोगुना कर 10% किया।

मंत्री नायडू ने (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कियाः 'इंडिगो के सभी रूट्स पर 10% कटौती जरूरी है, ताकि ऑपरेशन स्थिर हो और कैंसिलेशन कम हों। लेकिन सभी 138 गंतव्य कवर रहेंगे।' इंडिगो ने तुरंत सहमति जताई – 'हम 10% कटौती का पालन करेंगे, लेकिन सभी डेस्टिनेशन पर सर्विस जारी रहेगी।'

सीईओ एल्बर्स ने वीडियो मैसेज में कहाः– 'हम पैरों पर खड़े हो गए हैं। 6 दिसंबर को 1,500, 7 को 1,650, सोमवार–मंगलवार को 1,800+ उड़ानें उड़ीं। आज (9 दिसंबर) पूरी तरह स्थिर।' उन्होंने माफी भी मांगीः– 'निराशा के लिए खेद। प्राथमिकता फंसे यात्रियों को पहुंचाना था, अब रिफंड चल रहा।' 6 दिसंबर तक 100% रिफंड पूरा।

क्या हो चुका, क्या बाकी?

रिफंडः 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों का 100% रिफंड। कुल ₹827 करोड़ जारी। प्रक्रिया डेली जारी।

बैगः 9,000 में से 4,500 डिलीवर। बाकी 36 घंटे में।

कंपेंसेशनः लास्ट–मिनट कैंसिल पर मंत्रालय के पैसेंजर चार्टर के तहत कंपेंसेशन जरूरी। लेकिन इंडिगो चुप – डिटेल्स जल्द।

DGCA ने 15 दिनों की जांच शुरू की है – शो–कॉज नोटिस जारी, सीनियर लीडरशिप पर कार्रवाई संभव। नायडू ने लोकसभा में कहाः ' इंडिगो ने 1 दिसंबर की मीटिंग में समस्या नहीं बताई, लेकिन अब स्लॉट्स रिड्यूस होंगे।'

आम जनता पर असरः चिंता मत करो, फायदा ही होगा!

सबसे बड़ा सवाल – आपकी जेब पर क्या बोझ? अच्छी खबरः असर न के बराबर। इंडिगो 10% कटौती के बावजूद सभी 138 डेस्टिनेशन कवर करेगी। मतलब, लोकल फ्लाइट्स पर असर कम। लेकिन ये स्लॉट्स अन्य एयरलाइंस (जैसे एयर इंडिया, स्पाइसजेट) को मिल सकते हैं, जिससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। नतीजा? टिकट रेट्स में संतुलन, शायद सस्ते

पंजाब सीएम के दौरे के अंतिम दिन दक्षिण कोरिया में प्रभावशाली निवेश रोड शो को मिला सपोर्ट

(जीएनएस) ।पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा अपने दक्षिण कोरिया दौरे के अंतिम दिन आयोजित प्रभावशाली निवेश रोड शो को अग्रणी औद्योगिक कंपनियों की भागीदारी के साथ भारी प्रोत्साहन मिला और इन कंपनियों ने पंजाब में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई।

यहां व्यापारिक नेताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब को स्थिर एवं पारदर्शी शासन वाला तथा भविष्य के निवेश के लिए पूरी तरह तैयार राज्य के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब का मजबूत औद्योगिक इको–सिस्टम, विश्वसनीय और सस्ती बिजली, कुशल एवं मेहनती श्रमिक बल तथा बड़े बाजारों से सुगम संपर्क सुविधाएँ इसे निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाती हैं ।भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि पंजाब का शासन मॉडल निवेशक–अनुकूल है, जो कार्य–कुशलता और कारोबारी चक्र के दौरान पूर्ण सहयोग पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का विजन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दक्षिण

कोरिया के साथ प्रौद्योगिकी, नवाचार और परस्पर लाभकारी संबंधों से प्रेरित है। दक्षिण कोरियाई कंपनियों का स्वागत करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इससे नवाचार–आधारित औद्योगिक विकास, दीर्घकालिक संबंध और परस्पर लाभकारी साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और अनुसंधान क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं हैं।

अपना विजन साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की मजबूत आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से समृद्ध भविष्य सृजन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंजाब को साहस, मेहनत, उद्यमिता, रचनात्मकता और मजबूत सामुदायिक समझ वाली धरती के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा भारत के विकास, विशेष रूप से खाद्य उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पंजाब आधुनिक औद्योगिक, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के शासन एवं नियामक सुधारों को भी रेखांकित किया, जिनमें फास्टट्रैक पंजाब सिंगल–विंडो सिस्टम शामिल है, जिसमें 173 सेवाएं, ऑटो–डीम्ड मंजूरियां, पैन–आधारित व्यवसाय पहचानकर्ता और पंजाब बिजनेस राइट्स एक्ट में संशोधन शामिल हैं, जो समयबद्ध सैद्धांतिक मंजूरियों को सक्षम बनाते हैं। उन्होंने पंजाब के औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर भी प्रकाश डाला और बताया कि 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ग्राउंड इन्वेस्टमेंट पहले ही इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से सुनिश्चित किया जा चुका है।

सर्दियों में बालों को खुशबूदार बनाने के लिए हेयर परफ्यूम : शहनाज हुसैन

कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है ऐसे में हर महिला को बाल धोने में आलस आता है

कई बार हेयर वाश 5 -6 दिनों तक नहीं हो पता क्योंकि इस बात की ही उलझन रहती हैं कि किस दिन बाल धोने चाहिए

आजकल शादियों और पार्टियों का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर शादी या पार्टी का कोई न्यौता आ गया तो बाल धोना मजबूरी हो जाती है लेकिन आधा घण्टा उन्हें सूखने में लग जाता है

हालाँकि हेयर वाश बालों की हैल्थ के लिए काफी जरूरी माना जाता है लेकिन अगर आप बालों को धोने से परहेज कर रही हैं और आपको पार्टी में जाना जरूरी है तो हेयर परफ्यूम आपके बालों के लिए बेहतर बिकल्प है

हेयर परफ्यूम बालों को सुगन्धित करने के साथ है फ्रेश लुक देने में भी मदद करता है हेयर परफ्यूम बालों से आने बाली बदबू को रोकता है और रूखे , फ्रिजी और बेजान बालों पर असरदार साबित होता है

लेकिन असली सवाल है की हेयर परफ्यूम कैसे काम करता है और कितना सुरक्षित है

हेयर परफ्यूम का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसकी खुशबू आम परफ्यूम से हल्की होती है, इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करना मुश्किल होता है।

जिस तरह आप बॉडी परफ्यूम का इस्तेमाल करती हैं, ठीक उसी तरह बालों को खुशबूदार बनाने के लिए हेयर परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं ।यह बालों को अपनी खुश्बू से महकाता है और साथ साथ बालों को मॉइस्चराइज भी करता है जिससे बाल हेल्दी और तरो ताजा नजर आते हैं और बालों की बेहतर लुक नजर आती है हेयर परफ्यूम बालों को सुन्दर दिखाने के साथ ही लग्जरी टच जोड़ता है और आपको आत्मविश्वास तथा ताजगी महसूस करवाता है

कुछ लोग बॉडी परफ्यूम को ही बालों पर छिड़क देते हैं लेकिन उसमें अल्कोहल होता है जो बालों को और ज्यादा रूखा और बेजान बना देता है।

दूसरी ओर हेयर परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह आपके बालों के लिए ज्यादा सुरक्षित है। यह आमतौर पर पानी पर आधारित होता है, इसलिए यह आपके बालों को भारी नहीं बनाएगा और न ही उन्हें रूखा या चिपचिपा बनाएगा।

हालाँकि बड़ी नामी कम्पनियां बाजार में ब्राण्डेड हेयर स्प्रे बेचती हैं लेकिन अगर घर पर हर्बल हेयर स्प्रे बनाया जाये तो बेहतर होगा

1 -गुलाब की खुशबू का हेयर परफ्यूम

इस घर पर बने गुलाब.हेयर परफ्यूम से गुलाबों की रोमांटिक खुशबू का आनंद लें। गुलाब की मनमोहक

खुशबू आपके बालों को अद्भुत रूप से ताजा और सुगंधित महसूस कराएगी ।

गुलाब की खुशबु का हेयर परफ्यूम बनाने के लिए 2 चम्मच गुलाब का तेल, 1 चम्मच जोजोबा ऑयल और 5 चम्मच गुलाब जल को एक स्प्रे बोतल में डाल कर मिक्स करें। आपका होममेड गुलाब की खुशबू वाला हेयर परफ्यूम तैयार है। शादी या पार्टी में जाने से पहले इस हेयर परफ्यूम को बालों पर लगाएं। इससे न सिर्फ आपके बालों से अच्छी खुशबू आएगी बल्कि बालों को पोषण भी मिलेगा।

हेयर परफ्यूम को आप अन्य तरीकों से भी बना सकती हैं

2 - कांच के एक बर्तन में आधा चमच्च गुलाब जल और एक चमच्च बिच हेजल को अच्छे तरह मिला लें अब इस मिश्रण में पांच बूंदे गुलाब तेल मिला कर बने मिश्रण को स्प्रे बोतल में डाल लें यह हेयर स्प्रे तैयार है और आप इसे शादी या पार्टी में जाने से पहले प्रयोग कर सकती हैं

3 -हेयर परफ्यूम बनाने के लिए 14 कप होम मेड गुलाब जल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं अगर आप एलोवेरा जेल को थोड़ा ब्लेंड कर लेंगी तो अच्छा होगा। अब इसमें 10 बूंदें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की और 10 बूंदें जैस्मिन एसेंशियल ऑयल की मिलाएं।

इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर स्प्रे बॉटल में स्टोर कर फ्रिज में रखें।

4 -कांच के कटोरे में आधा कप गुलाब जल , चार बुंदे बेनीला अर्क , 20 बुंदे ग्रेप फ्रूट एसेंशियल आयल और 10 बूंदे जैस्मिन एसेंशियल आयल को एक साथ अच्छे से मिला लें अब इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में डाल कर फ्रिज में रख लें और अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग करें

हेयर परफ्यूम लगाने के लिए

सबसे पहले बोतल को अपने बालों से लगभग छह से आठ इंच की दूरी पर रखें। इसके बाद, हल्का स्प्रे करें ध्यान रहे कि यह बालों के बीचों.बीच और सिरों पर ज्यादा केंद्रित हो।

जड़ों की बजाय बालों के बीच की लंबाई और सिरे पर ध्यान दें, ताकि सुगंधित बाल उत्पादों का समान वितरण सुनिश्चित हो सके।

यह तरीका खुशबू को समान रूप से फैलाने में मदद करता है। इससे आपके बाल भारी नहीं होंगे और न ही कोई चिपचिपा निशान छोड़ेंगे।

बेहतर होगा अगर हेयर परफ्यूम को आप किसी ड्राई प्लेस रखेंगी

हेयर परफ्यूम को आप हफ्ता भर आराम से स्टोर कर सकती हैं वैसे अगर मौसम ठंडा है तो ये और भी ज्यादा चलेगा।

लेखिका अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेषज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में लोकप्रिय है

'धुरंधर' के बाद अब साउथ में जलवा बिखेरेंगे अक्षय खन्ना, 'महाकाली' से पहला लुक आया सामने

(जीएनएस) ।बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बने हुए हैं। रणवीर सिंह स्टारर स्पाई–एक्शन फिल्म 'धुरंधर' में जहां रणवीर मुख्य नायक के रूप में चमके, वहीं अक्षय खन्ना ने विलेन का दमदार रूप पर्दे पर उतारकर दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस, चाल–ढाल और गहन अभिनय ने फिल्म को एक अलग ऊंचाई दी है। सोशल मीडिया पर भी उनके किरदार की खूब सराहना हो रही है और फिल्म देखने वालों का कहना है कि अक्षय खन्ना ने अपने नेगेटिव रोल से कहानी में नई जान डाल दी।

इसी बीच, अक्षय खन्ना के

करियर को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। अभिनेता जल्द ही तेलुगु डेब्यू करने जा रहे हैं। वह निर्देशक प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की आगामी फिल्म 'महाकाली' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म को पूजा कोल्लुरु निर्देशित कर रही हैं और यह हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज होगी। 'महाकाली' में अक्षय शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं, जो पौराणिक और शक्तिशाली चरित्र होने के कारण फिल्म में मुख्य आकर्षण में से एक माना जा रहा है।

हालांकि मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक पहले जारी किया था, पर तब उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। 'धुरंधर' में अक्षय की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद, अब उनके 'महाकाली' वाले अवतार को लेकर उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है। अक्षय पहले भी 'छावा' में औरंगजेब की गहरी और प्रभावशाली भूमिका से सुर्खियां बटोर चुके हैं, इसलिए दर्शकों को उनसे नई उम्मीदें हैं।

दूसरी ओर, 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को लगभग ₹23 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म पहले सप्ताह में ही 100 करोड़ क्लब को पार कर चुकी है, और उम्मीद है कि वैश्विक स्तर पर यह जल्द ही ₹200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी।

फिल्म का दूसरा भाग 'धुरंधर 2' अगले वर्ष 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा, जिसके लिए दर्शकों में भारी उत्साह है। अक्षय खन्ना की बढ़ती लोकप्रियता और साउथ इंडस्ट्री में उनकी नई पारी उनके करियर को एक नए मुकाम की ओर ले जा रही है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से नवम्बर, 2025 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों से प्राप्त किया लगभग ₹140 करोड़ रुपये का जुमार्ना

एसी उपनगरीय लोकल से ₹2.40 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली

मुंबई, पश्चिम रेलवे बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अपने पूरे नेटवर्क पर व्यापक और सतत टिकट जांच अभियान निरंतर चला रही है। राजस्व हानि रोकने और यात्रा अनुशासन को सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, पश्चिम रेलवे के टिकट जांच स्टाफ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में सराहनीय एवं उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों के सक्रिय मार्गदर्शन में अत्यंत प्रेरित टिकट जांच स्टाफ ने मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर सेवाओं तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में कठोर जांच अभियान चलाए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य राजस्व लीकेज को न्यूनतम करना और यात्रा अनुशासन को मजबूत बनाना रहा है।

अप्रैल से नवम्बर, 2025 की अवधि में, 21.70 लाख से अधिक बिना टिकट/अनियमित यात्रियों का पता लगाया गया, जिसमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹140 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 50% अधिक है। नवम्बर, 2025 के दौरान ही 2.80 लाख से अधिक बिना टिकट/अनियमित यात्रा के मामलों का पता लगाकर ₹18.25 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% से अधिक की वृद्धि को दशार्ती है।

पश्चिम रेलवे द्वारा एसी उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी केंद्रित जांच अभियान चलाए गए। सामान्य टिकटधारकों द्वारा अनधिकृत यात्रा रोकने हेतु बार-बार औचक जांच की गई। अप्रैल से नवम्बर, 2025 के दौरान एसी लोकल सेवाओं में लगभग 75 हजार दंडात्मक मामलों का पता लगाकर ₹2.40 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 85% वृद्धि को दशार्ती है।

श्री विनीत ने आगे बताया कि टिकट जांच एक सतत जिम्मेदारी है, जिसमें कुशलता और विनम्रता दोनों आवश्यक हैं, और पश्चिम रेलवे को अपने समर्पित टिकट जांच स्टाफ पर गर्व है। ऐसे ही एक टिकट जांच स्टाफ सदस्य श्री अशुतोष कुमार सिंह, जो मुख्यालय, चर्चगेट स्थित फ्लाइंग स्क्वाड में उप मुख्य टिकट निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। नियमों एवं प्रक्रियाओं की उत्कृष्ट जानकारी के साथ, उन्होंने पिछले 18 वर्षों में लगातार उल्लेखनीय उत्साह और समर्पण के साथ कार्य किया है। जनवरी, 2025 से नवम्बर, 2025 तक मात्र 11 महीनों में उन्होंने 9200 से अधिक मामलों का पता लगाकर लगभग ₹1.08 करोड़ रुपये की अब तक की सर्वाधिक वसूली की है। उनका दैनिक औसत संग्रह लगभग ₹40,000 और प्रतिदिन औसतन 34 मामलों का पता लगाने का है। विशेष रूप से, 18 अक्टूबर, 2025 को उन्होंने एक ही दिन में 150 से अधिक मामलों का पता लगाकर ₹2.24 लाख रुपये की सर्वोच्च एकदिवसीय वसूली की, जो टिकट जांच स्टाफ के लिए प्रेरणादायक मानक स्थापित करती है।

पश्चिम रेलवे आम जनता से अपील करता है कि कृपया उचित एवं वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें।

पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत मिश्रित कृषि के लिए प्रोत्साहन

(जीएनएस) ।कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) मॉडलों के माध्यम से सतत कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है। इस योजना के अंतर्गत, फसलों/फसल प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि-वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि किसान अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें और चरम मौसमी स्थितियों से होने वाले प्रभावों को कम कर सकें।

नीति आयोग द्वारा 2025 में आरएडी कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि आरएडी हस्तक्षेप, जब साइट-उपयुक्त तरीके से बंडल और कार्यान्वित किए जाते हैं, तो वे संवेदनशील कृषि-जलवायु क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने में प्रभावी साबित हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप सूखा-प्रवण क्षेत्रों में अनुकूलन क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि इस कार्यक्रम का मृदा-नमी संरक्षण, विविध फसल प्रणालियों या भूदृश्य-आधारित विकास दृष्टिकोणों के माध्यम से जलवायु संबंधी दुष्प्रभावों के प्रति अनुकूलन बढ़ाने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आरएडी को राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से और 2022-23 से पीएम-आरकेवीवाई के एक भाग के रूप में कार्यान्वयन किया गया है। इसकी स्थापना के बाद से, आरएडी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आईएफएस अपनाने हेतु केंद्रीय सहायता के रूप में 2119.8397 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं जिससे 8.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 14.35 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं ।

आरएडी कार्यक्रम के अंतर्गत, आईएफएस अपनाने वाले किसानों की क्षमता निर्माण हेतु प्रति क्लस्टर 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) प्रदर्शनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थान-विशिष्ट आईएफएस मॉडलों को बढ़ावा देते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, केवीके ने 4416 प्रदर्शन आयोजित किए और 96,013 किसानों को विभिन्न आईएफएस मॉडलों पर प्रशिक्षित किया।

वर्ष 2025-26 के दौरान, आरएडी के अंतर्गत किसानों के क्षमता निर्माण सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 343.86 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई

नई ट्रेन से तीर्थ पर्यटन, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा

क्षेत्रों और संस्कृतियों के जोड़ती है देश की जीवन रेखा भारतीय रेल: वी सोमन्ना

(जीएनएस) रेल और जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस का आज नई दिल्ली स्थित रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखा कर शुभारंभ किया।

तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस शुरू किए जाने से कई दूरगामी लाभ होंगे। इससे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क को काफी मजबूती मिलेगी। यह श्रद्धालुओं के लिए आंध्र प्रदेश की दक्षिण तटीय पट्टी से शिरडी के लिए पहली सीधी ट्रेन सेवा है। यह ट्रेन भारत के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों, तिरुपति और शिरडी को सीधे जोड़ कर तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी।

इस नई ट्रेन से इसके मार्ग में तीर्थ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा यह क्षेत्रीय विकास में सहायक होगी। यह यात्रियों को सुरक्षित, आरामदेह और निर्बाध अंतरराज्यीय यात्रा का विकल्प मुहैया कराएगी। इससे तीर्थयात्रियों के समग्र रेल यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। इस साप्ताहिक ट्रेन से तीर्थयात्री निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन को एक तरफ की यात्रा पूरी करने में लगभग 30 घंटों का समय लगेगा।

श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस के शुभारंभ

को चार राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं है। यह देश की जीवन रेखा के रूप में क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ती भी है।

रेल और जल शक्ति राज्यमंत्री ने कहा कि अब तिरुपति और शिरडी सीधी ट्रेन सेवा से जुड़ गए हैं। यह ट्रेन नेल्लोर, गुंटूर, सिकंदराबाद, बीदर और मनमाड़ समेत 31 महत्वपूर्ण स्थानों पर रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से तीर्थ पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने के साथ ही इसके मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और सिकंदराबाद से सीधी कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। अपने मार्ग में यह एक महत्वपूर्ण शैव मंदिर परली वैजनाथ को भी जोड़ेगी।

श्री वी सोमन्ना ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 2014 से रेल अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का साझा औसत रेल बजट 886 करोड़ रुपए का था। यह 11 गुना बढ़ कर 2025-26 में 9417 करोड़ रुपए का हो गया। राज्य में 93000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम जारी है। आंध्र प्रदेश में 2014 से अब तक 1580 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गईं और 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा किया गया। राज्य में वर्तमान में 73 अमृत स्टेशन हैं। श्री सोमन्ना ने 800 फ्लाईओवरों और पुलों के निर्माण, 110 लिफ्ट और 40 एस्केलेटर लगाए जाने तथा 16 वंदे भारत (8 जोड़ी) और 6 अमृत भारत (3 जोड़ी) ट्रेन सेवाओं की शुरूआत का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे तिरुपति में तिरुपति अमृत स्टेशन समेत 312 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। प्रमुख जारी परियोजनाओं में तिरुपति-पकाला-कटपड़ी मार्ग पर 105 किलोमीटर का दोहरीकरण 1215 करोड़ रुपए के खर्च से किया जा रहा है। कुल 83 किलोमीटर की गुडूर-रेनिगुंटा तीसरी लाइन पर 875 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नादिकुड़ी-श्रीकालाहस्ती 310 किलोमीटर नई लाइन पर 5900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा, 287 किलोमीटर की विजयवाड़ा-गुडूर तीसरी लाइन पर 6235 करोड़ रुपए और 25 किलोमीटर की येरपेडु-पुडी बाईपास लाइन पर 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

आंध्र प्रदेश के सड़क और भवन तथा अवसंरचना और निवेश मंत्री श्री बीसी जनार्दन रेड्डी ने मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में हिस्सा लिया। इसमें उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में तिरुपति के सांसद डॉ मदिला गुरुमूर्ति, विधान परिषद सदस्य श्री बी कल्याण चक्रवर्ती, तिरुपति से विधानसभा सदस्य श्री ए श्रीनिवासुलु तथा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड के सदस्य श्री भानु प्रकाश रेड्डी भी शामिल थे।

भारत नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करेगा

(जीएनएस) ।भारत, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से, 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करेगा । चिकित्सा क्षेत्र के वैश्विक दिग्गज, नीति निमार्ता, शोधकर्ता और विशेषज्ञ पारंपरिक चिकित्सा में नवाचार, साक्ष्य-आधारित अभ्यास और भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श के लिए इस शिखर सम्मेलन में एक साथ भाग लेंगे।

आयुष मंत्रालय ने 8 दिसंबर 2025 को केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया था। श्री प्रतापराव जाधव ने अपने संबोधन में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व और वैज्ञानिक विश्वसनीयता तथा वैश्विक सहयोग को बढ़ाने में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की बढ़ती भूमिका

पर प्रकाश डाला।

दिल्ली में सीसीआरएएस का केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आयुर्वेदिक अनुसंधान और नैदानिक प्रगति का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉ. हेमंत पाणिग्रही ने बताया कि सीएआरआई के एकीकृत नैदानिक, मौलिक और नीतिगत अनुसंधान ने जीवनशैली से जुडे और गैर-संचारी रोगों के समाधान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि संस्थान के विशेष क्लीनिक, चल रहे शोध अध्ययन और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, साक्ष्य-आधारित पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन में मंत्रिस्तरीय चचार्एं, वैज्ञानिक पैनल, प्रदर्शनियां और वैश्विक ज्ञान-साझाकरण सत्र शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य विश्व भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को पारंपरिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करना है।

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय ने 56वां स्थापना दिवस मनाया: अपने आदर्श वाक्य 'उत्कृष्टता के माध्यम से विजय' की पुष्टि की

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय ने मित्र देशों के 660 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है

(जीएनएस) ।रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय (सीडीएम) ने 8 दिसंबर, 2025 को सिकंदराबाद, तेलंगाना में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिवस के उपलक्ष्य में, सीडीएम ने पर्पल पेसर्स और पर्पल पेडलर्स क्लबों के सहयोग से स्थापना दिवस दौड़ और साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया।

समारोह में महिला सशक्तीकरण में निवेश द्वारा जिम्मेदार नागरिकों का विकास (डीआरआईडब्ल्यूई) का समापन समारोह भी आयोजित किया गया, जो उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षुओं के जीवनसाथियों में नेतृत्व, उद्यमिता, सामाजिक जागरूकता और सशक्तीकरण विकसित करने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय के सहयोग से एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम है।

समारोह के एक भाग के रूप में, भारतीय नौसेना के बैंड 'सिम्फनी' ने एक विशेष प्रदर्शन दिया, जिससे कार्यक्रम में संगीतमय भव्यता आ गयी।

1970 में स्थापित, सीडीएम उच्च रक्षा प्रबंधन शिक्षा को लेकर तीनों सेनाओं के लिए एक प्रमुख संस्थान है। अपने प्रमुख पाठ्यक्रम 'उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम' (एचडीएमसी) के साथ, यह संस्थान रक्षा योजना और निर्णय प्रक्रिया में आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतों को एकीकृत करके सभी सेवाओं में संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक रहा है। सीडीएम ने मित्र देशों के 660 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने वैश्विक समझ और रक्षा कूटनीति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस अवसर पर, कमांडेंट सीडीएम, मेजर जनरल जी. श्रीनिवास ने सभी रैंकों, असैन्य रक्षा कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को बधाई दी और अपने आदर्श वाक्य - "उत्कृष्टता के माध्यम से विजय" की सच्ची भावना के अनुरूप रक्षा प्रबंधन शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सीडीएम की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस समारोह में अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

एआई-कॉपीराइट इंटरफेस पर कार्य-पत्र का पहला भाग प्रकाशित

(जीएनएस) ।उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कॉपीराइट कानून के अंतसंर्बंधों की जांच करते हुए अपने कार्य पत्र का पहला भाग प्रकाशित किया है। यह पत्र डीपीआईआईटी द्वारा 28 अप्रैल, 2025 को गठित आठ सदस्यीय समिति ("कमेटी") की अनुशंसाओं को शामिल करता है, जिसका उद्देश्य जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए विद्यमान कानून की पर्याप्तता का आकलन करना और आवश्यकता पड़ने पर कानून में संशोधन के लिए अनुशंसाएं करना है।

कार्य-पत्र में विद्यमान दृष्टिकोणों का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें व्यापक छूट, टेक्स्ट और डेटा-माइनिंग अपवाद, ऑप्ट-आउट अधिकार के साथ या उसके बिना, स्वैच्छिक लाइसेंसिंग, या विस्तारित सामूहिक लाइसेंसिंग शामिल हैं। इन सभी मॉडलों के संबंध में उपयुक्तता संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि कार्यपत्र में बताया गया है, कार्यपत्र एक नए नीतिगत संरचना का प्रस्ताव करता है जिसका उद्देश्य कंटेट क्रिएटर और एआई इनोवेटर के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है।

शून्य मूल्य लाइसेंस मॉडल को अस्वीकार करते हुए समिति का तर्क है कि इससे मानव रचनात्मकता के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएगा तथा मानव निर्मित सामग्री का दीर्घकालिक रूप से निम्न उत्पादन हो सकता है।

एक विकल्प के रूप में, समिति एक हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखती है जिसके अंतर्गत:

एआई डेवलपर्स को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए कानूनी रूप से एक्सेस की गई सभी सामग्री के उपयोग के लिए एक व्यापक लाइसेंस प्राप्त होता है, जिसके लिए व्यक्तिगत बातचीत की आवश्यकता नहीं होती है;

रॉयल्टी केवल एआई उपकरणों के व्यावसायीकरण पर ही देय होगी, जिसकी दरें सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये दरें न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी।

एक केंद्रीकृत तंत्र रॉयल्टी संग्रह और वितरण को व्यवस्थित करता है जिसका उद्देश्य लेनदेन लागत को कम करना, कानूनी निश्चितता प्रदान करना और बड़े तथा छोटे दोनों एआई डेवलपर्स के लिए समान पहुंच में सहायता करना है।

डॉ. राघवेन्द्र राव ने इसमें बहुमूल्य योगदान दिया, जिनका सहयोग कार्य पत्र तैयार करने में महत्वपूर्ण रहा।

सुश्री डी. श्रीप्रिया, श्री कुशल वधावन और सुश्री प्रियंका अरोड़ा ने भी समिति के सदस्यों को पेपर तैयार करने में सहायता की।

इस प्रकाशन की घोषणा करते हुए, डीपीआईआईटी ने प्रस्तावित मॉडल पर आम लोगों की प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हुए, 30 दिनों के लिए जनता और हितधारकों के परामर्श हेतु मसौदा तैयार किया है।

ट्राई ने आंध्र प्रदेश में एलुरु शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया

(जीएनएस) ।भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नवंबर 2025 में आंध्र प्रदेश लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के तहत एलुरु शहर के व्यापक शहरी मार्गों को कवर करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अपने स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) निष्कर्ष जारी किए। ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद की देखरेख में आयोजित इन ड्राइव परीक्षणों को विभिन्न उपयोग वातावरणों- शहरी क्षेत्रों, संस्थागत हॉटस्पॉट, ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों आदि में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच के लिए डिजाइन किया गया था।

11 नवंबर 2025 से 13 नवंबर 2025 के बीच , ट्राई की टीमों ने एलुरु शहर के 348.6 किलोमीटर क्षेत्र में ड्राइव टेस्ट और 8 हॉटस्पॉट स्थानों के लिए विस्तृत परीक्षण किए। मूल्यांकन की गई तकनीकों में 2जी, 3 जी, 4 जी और 5 जी शामिल थे, जो विभिन्न हैंडसेट क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव को दर्शाते हैं। आईडीटी के निष्कर्षों से सभी संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी)

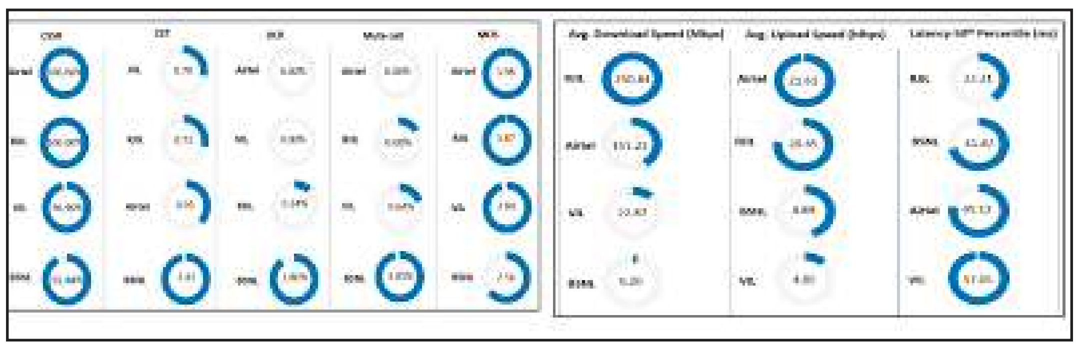

को अवगत करा दिया गया है।

मूल्यांकित प्रमुख पैरामीटर:

) वॉयस सेवाएं: कॉल सेटअप सफलता दर (सीएसएसआर), ड्रॉप कॉल दर (डीसीआर), कॉल सेटअप समय, कॉल साइलेंस दर, स्पीच गुणवत्ता (एमओएस), कवरेज।

ख) डेटा सेवाएं: डाउनलोड/अपलोड थ्रूपुट, विलंबता, जिटर, पैकेट ड्रॉप दर और वीडियो स्ट्रीमिंग विलंब।

एलुरु शहर और आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क गुणवता का सारांश नीचे दिया गया है:

कॉल सेटअप सफलता दर- एयरटेल, बीएसएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल की ऑटो-सिलेक्शन मोड (5जी/4जी/3जी/2जी) में कॉल सेटअप सफलता दर क्रमशः 100.00प्रतिशत, 92.84प्रतिशत, 100.00प्रतिशत और 96.90प्रतिशत है।

ड्रॉप कॉल दर - एयरटेल, बीएसएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल ड्रॉप कॉल दर ऑटो-सिलेक्शन मोड में क्रमशः 0.00प्रतिशत, 1.80प्रतिशत, 0.24प्रतिशत और 0.00प्रतिशत है

एलुरु शहर में, मूल्यांकन में नरसापुर, दग्गुलुरु, भीमावरम, पिप्पारा, ताडेपल्लीगुडेम, गुंडुगोलानु, जंगारेड्डीगुडेम, चिंतालपुडी, लिंगपालेम, विजयरी, डेंडुलुरु, पांगिडीगुडेम, कामवारापु, कैकालुरु, कालीदिंडी, मोगाल्टुरु और आसपास के क्षेत्र शामिल थे।

भारतीय डाक ने कोट्टायम के सीएमएस कॉलेज में केरल के प्रथम आधुनिक जेन-जेड डाकघर विस्तार काउंटर का अनावरण किया

(जीएनएस) ।भारतीय डाक ने केरल के कोट्टायम स्थित सीएमएस कॉलेज में अपनी तरह के पहले जेन-जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन किया। यह नई पीढ़ी के लिए आवश्यक आधुनिक डाक सेवाओं से जुडाव को परिभाषित करेगा। इस सुविधा का उद्घाटन केरल मध्य क्षेत्र के डाक निदेशक (डीपीएस) श्री एन.आर. गिरि ने किया।

भारतीय डाक और सीएमएस कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन

'छात्रों का, छात्रों द्वारा, छात्रों के लिए' के मूल दर्शन के साथ परिकल्पित इस पूरे स्थान की कल्पना, योजना और सह-निर्माण सीएमएस कॉलेज के छात्रों द्वारा भारतीय डाक अधिकारियों के सहयोग से किया गया, जो रचनात्मकता, स्थिरता और सेवा का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है।

यह डाक विस्तार काउंटर एक जीवंत, युवा, प्रकृति से ओतप्रोत स्थान है जो आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों का सहज मिश्रण है। इसका परिणाम एक आधुनिक डाक विस्तार काउंटर है जो एक कार्य कैफे, एक हरित कोना और एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है—और साथ ही प्रकृति के साथ सामंजस्य के कॉलेज के सिद्धांतों के प्रति भी समर्पित है।

सीएमएस कॉलेज में नवनिर्मित जेन जेड थीम वाला डाक विस्तार काउंटर।

जेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर की मुख्य विशेषताएं

पिकनिक-टेबल शैली की व्यवस्था और एक ऊर्ध्वाधर उद्यान के साथ प्रकृति-थीम वाला बैठने का क्षेत्र, एक ताजा और शांत वातावरण प्रदान करता है। नवीनीकृत टायरों से बनी अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था, स्थिरता और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं के प्रति छात्रों कीप्रतिबद्धता को दशार्ती है।

लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों के लिए चार्जिंग पॉइंट से सुसज्जित कार्य-अनुकूल काउंटर हैं।

मनोरंजन और विश्राम का कोना,

दियोरिया उपकेंद्र पर बिजली बिल राहत शिविर सफल

22 बकाएदारों ने जमा किए 1.80 लाख रुपये - गांव-गांव पहुंचकर वसूली का अभियान, 31 दिसंबर तक चलेगा पहला चरण

(जीएनएस) ।पीलीभीत, दियोरिया कला विद्युत उपकेंद्र पर मंगलवार को बिजली बिल राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 22 बकाएदारों ने अपना बकाया बिल जमा किया, जिससे 1.80 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह अभियान बिजली विभाग की वसूली को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है।शिविर का विवरण:शिविर में बकाएदारों को बिना ज़ुमार्ने के बिल जमा करने का मौका दिया गया। एसडीओ जगदीश सिंह ने बताया कि पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान गांव-गांव जाकर शिविर लगाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण आसानी से भुगतान कर सकें। उपकेंद्र पर एसडीओ जगदीश सिंह, जेई लक्ष्मी कांत, टीजी2 कुलदीप व संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। एक बकाएदार ने कहा, "शिविर से बिल जमा करना आसान हो गया, अब बिजली कटौती का डर नहीं।"अभियान का उद्देश्य:विभाग ने लक्ष्य रखा है कि बकाया वसूली से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। एसडीओ बोले, "ग्रामीणों को राहत मिलेगी, विलंब शुल्क माफ।" आने वाले दिनों में अन्य उपकेंद्रों पर भी ऐसे शिविर होंगे।

शिक्षक ने लोहे की रॉड से सिर पर बार कर युवक को किया घायल पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार।

पीलीभीत बिलसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव के प्राथमिक विद्यालय के एक दबंग शिक्षक ने बेबजह गांव के ही एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर किया गम्भीर घायल।

मामला क्षेत्र के गांव कनपरी का प्रकाश में आया है पीड़ित ने बताया है कि गाँव के प्राथमिक विद्यालय के एक दबंग शिक्षक ने बेबुनियाद जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड से सिर पर वार करके गंभीर चोट पहुँचाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने कहा है कि विद्यालय के पास ही कुछ खाली जगह पर पीड़ित का न तो कोई कब्जा है और न ही कोई सामान रखा है फिर भी उक्त शिक्षक द्वारा पीड़ित के साथ लगातार विवाद व झगड़ा किया जा रहा है। स्कूल के बाहर शिक्षक ने पीड़ित को बुलाकर गाली-गलौज की। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो शिक्षक आग-बबूला होकर लोहे की रॉड लेकर विद्यालय के बाहर आया तथा पीड़ित पर हमला कर दिया, जिससे पीड़ित के सिर पर बार किया पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया जिस कारण सिर से अत्यधिक रक्त बहा, जिससे पीड़ित अचेत हो गया।घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने 112 डायल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस द्वारा पीड़ित को उपचार हेतु समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहाँ पीड़ित का उपचार किया गया, लेकिन घटना की गंभीरता के बावजूद, शिक्षक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की साठगांठ के दबाव के कारण अब तक पीड़ित की शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है।पीड़ित ने पुलिस पर चालान करने का भी लगाया आरोप,उलटे शिक्षक द्वारा पीड़ित को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे पीड़ित और उसका परिवार अत्यंत भयभीत है। प्राथमिक विद्यालय के पद का दुरुपयोग करते हुए वह पीड़ित को नीचा दिखाने और परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करके शिक्षक के विरुद्ध थाना बिलसंडा को उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश देने की गुहार लगाई है।

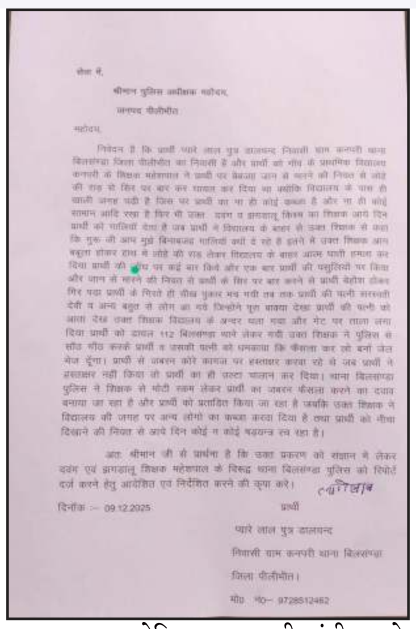

पानी का निकास न होने के कारण सड़क पर जल भराव की समस्या।

छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में हो रही बड़ी समस्या।

(जीएनएस) ।पीलीभीत
पूरनपुर ।पानी का निकास न होने के कारण सड़क पर जल भराव की समस्या से ग्रामीण परेशान।प्राथमिक विद्यालय के पास जल भराव की समस्या, छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कत हो रही है।

पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत पटिहन में प्राथमिक विद्यालय के पास जल भराव की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस समस्या के कारण छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। जल भराव के कारण बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी हो सकती है और उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते नालियों का गंदा पानी सड़क पर भर रहा है हालांकि पास में प्राथमिक विद्यालय और शिव मंदिर है

जिसे छोटे-छोटे बच्चों एवं ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है

ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारी को जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन को इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए।

सेहरामऊ क्षेत्र के जगतपुर गांव में दबंग युवक ने बिना परमिट तालाब खाली कराया

ग्रामीणों में आक्रोश - जानवरों के पानी का संकट, प्रशासन से मांग: कार्रवाई करें

(जीएनएस)। पीलीभीत, सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में दबंग युवक द्वारा तालाब को इंजन से खाली कराने का मामला गरमा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना किसी परमिट के यह अवैध कार्रवाई की गई, जो तालाब से जुड़े पुराने विवाद को फिर उभार रही। गांव के जानवरों व पशु-पक्षियों के लिए एकमात्र पानी स्रोत होने से ग्रामीण चिंतित हैं।

घटना का पूरा विवरणः

जगतपुर गांव के मुख्य तालाब को दबंग युवक ने मछली पालन या अन्य उद्देश्य से खाली कराने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने बताया कि इंजन की मदद से पानी निकाला जा रहा, लेकिन परमिशन न होने से अवैध है। तालाब पहले से भूमि विवाद में उलझा रहा, जहां ग्रामीणों ने विरोध किया था। एक ग्रामीण बोले, "दबंग ने किसी की सुनवाई न की, तालाब सूखा तो पशु भटकेंगे।" खाली होने से मछलियां मर रही, पर्यावरण को नुकसान। ग्रामीण तालाब किनारे जमा हो विरोध जता रहे।

ग्रामीणों का विरोध व अपील:

दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील व पुलिस को शिकायत दी। उनका कहना है, "तालाब सामुदायिक संपत्ति, बिना अनुमति खाली न हो। जानवरों का क्या?" महिलाओं ने चेतावनी दी - कार्रवाई न हुई तो धरना देंगे। ग्राम प्रधान बोले, "परमिट जरूरी, दबंगों पर अंकुश लगे।"

जनता के स्वास्थ्य के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं विधायक ने सदन में उठाया मेडिकल उपकरण घोटाले का मुद्दा

(एजेंसी)।

धनबाद। विधानसभा में पार्टी के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आज झारखंड विधानसभा सत्र में सदन में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल एस एन एम सी एच, धनबाद में हुए गंभीर अनियमितता के मामले को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को चलने में सहायता के लिए आथोर्पेडिक कैलीपर खरीदने हेतु जारी टेंडर के बावजूद, विभाग ने उसकी जगह वॉर्नियर कैलीपर (मापने वाला उपकरण) खरीदकर सप्लाई करा दिया जो पूरी तरह अलग उपकरण है और मरीजों के उपयोग में नहीं आता। विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि यह मामला छोटा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का हर निर्णय सीधे जनता के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। जनता के पैसे की बबार्दी और मरीजों के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब इस पर सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी ने इसे 'छोटा मामला' कहकर टालने की कोशिश की, तो विधायक श्री सिन्हा ने कड़ा ऐतराज जताते हुए स्पष्ट कहा जनता का पैसा और जनहित से जुड़ी योजनाएँ कभी छोटी नहीं हो सकतीं। धनबाद की जनता ने मुझे सवाल पूछने के लिए भेजा है और मैं हर अनियमितता पर सवाल पूछता रहूँगा। विधायक श्री सिन्हा की प्रमुख मांगें इस पूरे मामले की गंभीरता पूर्वक तत्काल जाँच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। गलत उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी पर सख्त दंडात्मक कदम उठाया जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। अंत में विधायक श्री राज सिन्हा ने कहा कि सरकारी तंत्र यदि अपने कर्तव्य से चूकेगा, तो जनता का प्रतिनिधि होने के नाते वे सदन से लेकर सड़क तक हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।

जब भगत सिंह 'वंदे मातरम' बोल रहे थे, आरएसएस क्या कर रहा था?' -संजय सिंह

नई दिल्ली, 9 दिसंबर 2025 :

राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर हुई विशेष चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'वंदे मातरम' का नारा लगाने वाले शहीदों की कुबार्नी पर जिनका कोई इतिहास नहीं, वे आज देशभक्ति के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि सरकार वंदे मातरम् की आड़ में असली मुद्दों — बेरोजगारी, महंगाई, दलित-पिछड़ों पर अन्याय और देश की आर्थिक लूट — से ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम् मातृभूमि की वंदना है, लेकिन जो मातृभूमि को बेच रहे हैं, वे उसकी वंदना नहीं, अपमान कर रहे हैं।'

संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार 'देशभक्ति' की बातें करती है लेकिन एक रुपये में अपने मित्र को हजारों एकड़ जमीन और लाखों पेड़ दे देती है। उन्होंने कहा — 'रेल, सेल, तेल और देश की जमीन बेचकर मातृभूमि की वंदना नहीं हो सकती। जो लोग देश बेच रहे हैं, वे वंदे मातरम् का अपमान कर रहे हैं।'

भगवान श्रीराम ने नहीं कहा कि जनता को अंधेरे में रखो

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा कि जब व्यापारी बिजली की समस्या लेकर पहुंचे तो मंत्री ने बस 'जय श्रीराम' बोलकर गाड़ी बढ़ा दी। उन्होंने सवाल किया — 'क्या भगवान राम ने कहा है कि निकम्मे बनो और जनता को अंधेरे में रखो?'

आरएसएस का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं

संजय सिंह ने आरएसएस पर आजादी के आंदोलन से भागने का आरोप लगाते हुए कहा — 'जब भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकउल्ला, बिस्मिल और खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर वंदे मातरम् का नारा लगा रहे थे, तब आरएसएस क्या कर रहा था? उन्होंने कहा कि आरएसएस ने न तो कभी तिरंगा फहराया, न राष्ट्रगान स्वीकार किया, न वंदे मातरम् बोला। 1949 में आरएसएस के अखबार 'ऑगेर्नाइजर' में राष्ट्रगान का विरोध किया गया था — देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

आरएसएस ने 13 साल मुकदमा लड़ा क्योंकि आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया था

संजय सिंह ने कहा कि 'तीन देशभक्त युवकों ने जब आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया, तो संगठन ने उन्हीं के खिलाफ एफआईआर कर दी और 13 साल तक मुकदमा लड़ा। उन्होंने कहा कि जो तिरंगे और राष्ट्रगान का विरोध करें, वे भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते।

भाजपा कर रही है वोट की चोरी, 3 करोड़ मतदाता सूची से गायब करने की साजिश

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में रक्क्र फॉर्म के नाम पर करीब 3 करोड़ वोट चोरी करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 'आपने तो वोट की भी चोरी कर ली है। जिस तरह फिल्मों में डाकू 'जय भवानी' बोलकर गांव लूटते थे, भाजपा 'वंदे मातरम' बोलकर लोकतंत्र लूट रही है।'

बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय पर सरकार मौन

संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, दलितों-पिछड़ों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा — 'देश आज 200 लाख करोड़ रुपये के कर्ज तले दबा है, और सरकार देशभक्ति का नाटक कर रही है।'

हम वंदे मातरम् और भारत माता की जय कहते रहेंगे, लेकिन देश को लूटने नहीं देंगे

अंत में संजय सिंह ने कहा — 'हम वंदे मातरम् कहेंगे, भारत माता की जय कहेंगे, जय हिंद कहेंगे — लेकिन किसी को भी वंदे मातर के नाम पर देश लूटने नहीं देंगे।'

पौराणिक हंस तीर्थ संगम क्षेत्र प्रयागराज

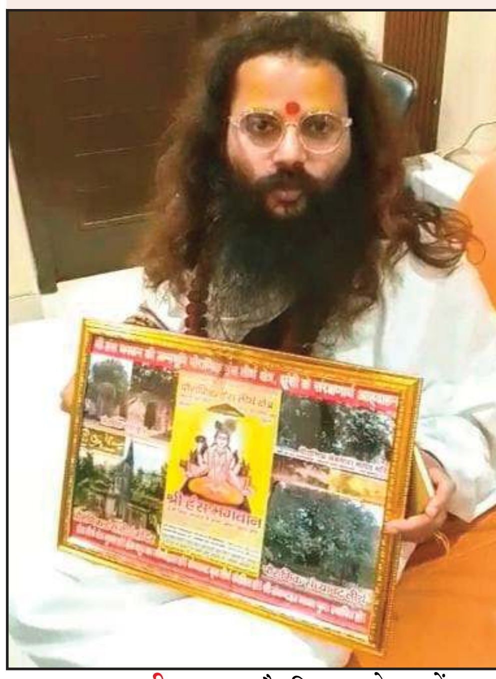

प्रयागराज (जीएनएस) ।पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र का ज़िक्र आते ही उत्साह बढ़ जाता है! प्रयागराज का यह स्थल धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद रोचक माना जाता है।

प्रयागराज में हंस तीर्थ एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, जहाँ पौराणिक मान्यता के अनुसार देवीझ्र देवताओं का वास और हंस (जो भगवान ब्रह्मा का वाहन भी माना गया है) द्वारा तपस्या का वर्णन मिलता है।

कहा जाता है कि यहाँ हंस स्वरूप में देवताओं ने तप किया था।

यह स्थान त्रिवेणी संगम क्षेत्र से जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा माना जाता है।

प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख 'हंस तीर्थ' के रूप में मिलता है, जहाँ शुद्धि, मोक्ष और पवित्रता की कामना की जाती थी।

हंस तीर्थ क्षेत्र को सामान्यतः संगम क्षेत्र, उसके आसपास की पवित्र भूमि से जोड़कर देखा जाता है।

कई स्थानीय मान्यताओं में इसे त्रिवेणी के पास का एक तपस्थान कहा जाता है।

खबर का हुआ असर सीज बिल्डिंग पर जारी काम पर नाका पुलिस ने कसा शिकंजा

(जीएनएस) ।लखनऊ। आपको बताते चलें गणेश गंज चौकी क्षेत्र में एलडीए द्वारा सीज की गई बिल्डिंग पर निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जोन 6 की जोनल अधिकारी वंदना पांडे द्वारा बिल्डिंग सीज करने के बाद थाना नाका पुलिस को बाकायदा पत्र भेजकर अवगत कराया गया था और पुलिस अभिरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। लेकिन इसके बावजूद दबंग बिल्डर ने एलडीए के आदेशों को दरकिनार करते हुए निर्माण कार्य दोबारा शुरू करा दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद काम जारी था, जिससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं क्षेत्रीय पुलिस एलडीए के आदेशों को नजरअंदाज तो नहीं कर रही? सूत्रों का दावा है कि बिल्डर लगातार दबाव बनाकर निर्माण कार्य करा रहा था और पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई न होने से उसकी मनमानी बढ़ती जा रही है स्थानीय निवासियों ने एलडीए और उच्च पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि सीज बिल्डिंग पर जारी अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए और आदेश की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्रकार द्वारा दूरभाष से वार्ता करने पर नाका थाना प्रभारी श्रीकांत राय ने बताया की गणेशगंज रोड पर गुलाटी पीपल वाले के सामने जो कमर्शियल अवैध निर्माण चल रहा था उस पर बिल्डर को समझाते हुए उचित कार्रवाई करके काम रुकवा दिया गया है। वहीं खंजर सूत्रों की मानें तो वही पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करके अन्दर काम जारी है।

गैस रिसाव पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर प्रभावित लोगों को राहत दिलाई

(जीएनएस) ।धनबाद। लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन (आरसीएमयू) की वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीमती अनुपमा सिंह ने आज गैस रिसाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा सर्वप्रथम जहरीली गैस रिसाव की घटना में निर्दोष लोगों की मृत्यु पर मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। यह अत्यंत दुखद और हृदयविदारक घटना है। मैं केंद्र सरकार की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल से मांग करती हूं कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का उचित मुआवजा दिया जाए। राज्य की हमारी अबुआ सरकार ने सर्वप्रथम घोषित 4-4 लाख रुपये दिए जाएगे उन्होंने आगे कहा गैस रिसाव को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत रोका जाए, न कि विस्थापन के नाम पर लोगों को डराया धमकाया ना जाए। यहां के लोग कई पीढ़ियों से इसी क्षेत्र में रहकर अपना आजीविका चला रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि धनबाद जैसे शहर में डीजीएमएस, सीआईएमएफआर और आईएसएम जैसे राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान होने के बावजूद गैस रिसाव जैसी गंभीर समस्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा यह सरासर गलत है। दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने अनुपमा सिंह को बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है, गैर-कानूनी ढंग से कोयला निकासी हो रही है, तथा चानक में लगे वेंटिलेशन फैन हटाए जा चुके हैं, जिसके कारण अंदर ही अंदर गैस का दबाव बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि हेवी ब्लास्टिंग से यहां रहने वाले लोगों में लगातार भय का माहौल बना रहता है और धूल प्रदूषण की समस्या अलग से परेशान कर रही है। श्रीमती सिंह ने प्रशासन से मांग की है की प्रशासन बीसीसीएल एवं आउटसोर्सिंग कंपनियां सख्त कार्रवाई करे सुरक्षा के सभी मापदंडों के अनुरूप कार्य होये और यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय लोगों को विस्थापन के नाम पर डराया न जाए। यहां रहने वाले परिवारों को सभी सुविधाएं, सुरक्षा और संरक्षण दिया जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को तुरंत रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। केंदुआ मटकुरिया बैंक मोड़ जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र एक से दो किलोमीटर की दूरी में ही स्थित है इसकी चपेट में आए, तो हजारों जानें खतरे में पड़ सकती हैं इसलिए यह मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है इसलिए बीसीसीएल प्रबंधन एवं प्रशासन इसे गंभीरता से संज्ञान में लें दौर में वरिष्ठ कांग्रेसी रामगोपाल भुवनिया, जयप्रकाश चौहान, अन्नु पासवान, मनुवर हुसैन, लक्ष्मण तिवारी, सतपाल सिंह ब्रोका, गुड्डू खान, अच्छेयवर प्रसाद, प्रमोद यादव, बिट्टू सिंह, संजय पासवान, सौरभ पाण्डेय, रहे शामिल।

बीसीसीएल प्रबंधन कांग्रेस नेत्री श्रीमती अनुपमा सिंह